महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के सफल प्रयास

महिला सशक्तिकरण का सीधा मतलब है महिलाओं को शक्ति और अधिकार देना। इसके लिए हमें अपने समाज में कई तरह के बदलाव लाने पड़ेंगे और महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का दर्जा देना होगा। देश को पूरी तरह से विकसित बनाने तथा विकास के लक्ष्य को पाने के लिये महिला का पूरी तरह से सशक्त होना बहुत जरुरी है। इस सन्दर्भ में महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि जब तक हमारे देश की सभी महिला और पुरुष एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का पूरी तरह से विकास नहीं होगा।

हरि भगवान शर्मा

बहुत पहले समय से ही भारतीय समाज में पुरुषों और महिलाओं में भेद किया जाता रहा है। यह सर्वविदित है कि महिलाएँ पुरुषों से प्रत्येक क्षेत्र में काम करने का अधिक सामर्थ्य रखती हैं, फिर भी महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती और उनकी क्षमता को दबाया जाता है। सभी कार्यों में उनकी भागीदारी होते हुए भी अधिकार नहीं दिए जाते। आजकल हमारे समाज में महिलाओं को अधिकार देने की बातें तो हो रही हैं, परन्तु इन अधिकारों से भी शहरी महिला ही लाभान्वित हो रही हैं, जबकि ये अधिकार ग्रामीण महिलाओं को भी प्रदान किये जाने चाहिए। ग्रामीण महिलाएँ अपने घरों को संभालने के साथ–साथ खेत–खलिहानों एवं अन्य सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं।

ग्रामीण महिलाओं ने आज तक किसी भी तरह की सुविधा तथा अधिकार की मांग नहीं की हैं। ऐसे में समाज और राष्ट्र हित में यहां के सभी जिम्मेदार नागरिकों का यह दायित्व है कि ग्रामीण महिलाओं को ज्यादा–से–ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराए। साथ ही, ऐसी भावना का विकास किया जाए, जिससे समुदाय में यह सोच विकसित हो सके कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो और जिससे देश का चहुंमुखी विकास संभव हो सके। ग्रामीण महिलाओं के विकास के उद्देश्य से सरकार ने कई योजनाएँ चलाई हुई हैं, जिनको सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

महिलाओं की कार्यक्षमता एवं बुद्धिमत्ता किसी भी दृष्टि से कम नहीं होती। इसके बावजूद भी यथार्थ के धरातल पर भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है और उनके अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बहुत असंतोषजनक है। अत्यधिक घरेलू, कृषि एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी भारत में महिलाओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है।

संवैधानिक अधिनियम के 73वें संशोधन 1993 में पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों पर (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्) महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिसमें ऐसी व्यवस्था है कि पंचायती राज संस्थाओं के एक–तिहाई सदस्य तथा अध्यक्ष महिलाएँ होना अनिवार्य हैं। सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण महिलाओं की ग्राम विकास में

भागीदारी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें ग्रामीण महिलाओं को विकास में भागीदार बनाने के लिए योजनाएँ बनातीं और कार्यान्वयन करती रहती हैं, जिससे निकट भविष्य में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ सकेगा।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को नाममात्र के लिये भागीदार तो बनाया गया, लेकिन इन सभी संस्थाओं के किसी भी कार्य में स्वतंत्र निर्णय लेने का न तो अधिकार दिया गया और न ही कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी। ज्यादातर पंचायतों में महिला सरपंच एवं पंच की ताकत उनके पति द्वारा हथिया ली जाती है और सभी कार्यों में उनकी मनमानी चलती रहती है, जिसके कारण महिलाएँ समाज हित में कोई भी निर्णय लेने में या कार्य करने में आगे नहीं आ पाती हैं और पंचायत के कार्यों को करने में अपने पतियों पर निर्भर रहती हैं। विभिन्न ग्रामीण योजनाओं का महिलाओं के सक्रिय योगदान के बिना सफल होना असंभव है। कोई भी विकास कार्य या किसी भी समाज की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी अपनी अहम् भूमिका निभाती है। इसी समस्या को केन्द्र में रखते हुए सहगल फाउंडेशन ने महिला संगठन के गठित करने की योजना बनाई और इस संगठन को सशक्त करने के लिए सफल प्रयास किये गए।

महिला संगठन महिलाओं का ऐसा समूह है, जो ग्रामीण विकास के कार्यों को मूर्त रूप देने के लिये सहगल फाउंडेशन द्वारा गठित किया गया। साल 2014 में 'नूहं जिले के पांच ब्लॉकों--नगीना, नूंह, तावडू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में महिला संगठन बनाये गए। इन महिला संगठनों के सदस्य मुख्यतः पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, स्कूल समिति की महिला सदस्य होती हैं। इन संगठनों में सदस्य बनाने के लिए महिलाओं को उनकी बौद्धिक योग्यता एवं जिम्मेवार नागरिक के आधार पर परखकर चुना गया। ये संगठन सहगल फाउंडेशन से प्रशिक्षण लेकर इतने सक्षम बन गए हैं कि अपने ग्राम स्तर की सभी समस्याओं को मिलजुलकर हल करने में निपुण और नूंह जिले में एक मिसाल बन गए हैं।

ग्राम विकास हित में महिला संगठन के द्वारा किये गए सफल कार्यों की कामयाबी की कई कहानियाँ हैं, जिनमें से कुछ कहानियाँ अविश्वसनीय हैं, जिसमें संगठन ने अपने अथक प्रयास से ग्रामीण समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण काम किये। महिला संगठन की कार्यक्षमता एवं सफलता की यह मात्र एक मिसाल नहीं है,. अपितु प्रमाण है कि राष्ट्र के विकास में महिलाएँ सभी स्तरों पर अग्रसर होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान कर सकती हैं।

सहगल फाउंडेशन भी 15 वर्षों से हरियाणा के पिछड़े जिले नूंह में ग्रामीण विकास के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2015 में इस जिले के सभी 5 खंडो में खंड स्तर पर 5 महिला संगठनों का गठन किया गया। इन पांच महिला संगठनों के गठन के उपरान्त संगठन के सदस्यों ने खुद की पहचान के लिये अलग-अलग नाम रखे। ब्लॉक नगीना के संगठन ने शक्ति, ब्लॉक नूंह के संगठन ने रोशनी, ब्लॉक फिरोजपुर झिरका के संगठन ने हरा-भरा, ब्लॉक पुन्हाना के संगठन ने उजाला तथा ब्लॉक तावडू के संगठन ने एकता संगठन जैसे नाम रखे।

महिला संगठन में नूंह जिले के सभी 5 खंडों में से 100 गाँवों का चयन किया गया, जिसमें प्रत्येक गाँव से कम--से-कम 2 सदस्यों का चुनाव कर कुल 207 सदस्यों का चयन किया गया। चयनित सदस्यों को ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं के कार्यों एवं जिम्मेदारियों के विषय में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। कुल 37 प्रशिक्षण सत्रों में 207 सदस्यों के अतिरिक्त 862 अन्य ग्रामीण महिलाओं एवं पुरूषों ने भी भाग लिया। इसके साथ-साथ ग्राम स्तर पर भी प्रत्येक गाँव से 5-10 सदस्यों को लेकर प्रगति समूह बनाये गए। इन समूहों के लिए कुल 100 गांवों से 2535 सदस्यों का चयन किया गया, जिनका कार्य महिला संगठनों के साथ मिलकर ग्रामीण विकास के कार्यों में सहयोग करना है। सहगल फाउंडेशन ने इन प्रगति समूहों के सशक्तिकरण के लिए भी 645 प्रशिक्षण सत्रों एवं 311 बैठकों का आयोजन किया, जिसमें प्रगति समूह एवं महिला संगठन के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य ग्रामीणों, मसलन कुल 6318 संगठन सदस्यों एवं ग्रामीणों ने भाग लिया।

महिला संगठन के सदस्यों का चुनाव ग्राम स्तरीय संस्थाओं के पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों में से ही किया गया। इस संगठन में ग्राम पंचायत की महिला पंच या सरपंच, स्कूल प्रबंधन समिति की महिला तथा ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को विशेषतः इसलिए शामिल किया गया, ताकि संगठन में सभी ग्रामीण संस्थाओं से महिलाओं की अधिक-से-अधिक भागीदारी संभव हो सके और ग्राम विकास हित में निर्णय लेना सुगम हो सके।

महिला संगठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तरीय

संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों को प्राप्त करने हेतु जागरूक करना तथा ग्रामीण समाज के उत्थान में उनकी भूमिका बढ़ाना है। साथ ही, महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जिसके माध्यम से वे एक–दूसरे के साथ अपनी उपलब्धियों को साझा कर सकें, एक–दूसरे के अनुभवों से सीख लें और इनका उपयोग अपने गाँव के विकास में कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को निर्धारित किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए चलाई गयी सरकारी योजनाओं को लागू करने एवं ग्रामीण विकास कार्यों को उत्तम ढंग से करवाने/गाँव में पीने योग्य पानी का उचित प्रबंध एवं शौचालय का निर्माण करवाने/सरकारी स्कूल में पीने योग्य पानी का बेहतर प्रबन्ध और लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालयों का निर्माण करवाने और बच्चों एवं महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ–साथ शिशुओं के जन्म प्रमाण–पत्र बनवाने के कार्य भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को लाडली योजना की राशि और विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन दिलवाने में मदद करना भी जुड़े हैं।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में फाउंडेशन द्वारा किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप महिला संगठन ने वर्ष 2015 में स्कूल प्रबंधन समिति के पुर्नगठन में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया, फलतः संगठन के 43 सदस्य सभी खंडों में स्कूल प्रबंधन समिति में चयनित हुए। स्कूल प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य स्कूल में आधारभूत सुविधाओं के साथ–साथ शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करते हुए 0–14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करना है। संगठन की इन सदस्यों ने सहगल फाउंडेशन द्वारा दी गई जानकारियों का उपयोग कर अपनी–अपनी स्कूल प्रबंधन समितियों में सक्रिय योगदान दिया और अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा हेतु समय–समय पर उचित निर्णय लिए।

सहगल फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट 2015 के अनुसार–नूंह जिले के 22 गाँवों में कुल 18 लाख रुपये से अधिक धनराशि का स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा व्यय किया गया, जिसका उपयोग महिला संगठन के साथ मिलकर प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों के भवन और शौचालय निर्माण, सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार निर्माण एवं मरम्मत, रंगाई–पुताई जैसे कार्यों में किया गया। इसके अलावा इसी वर्ष ही पंचायती राज संस्थाओं के सरकारी फण्ड से 35 गांवों में कुल 1.50 लाख रुपये का व्यय किया गया, जिसका उपयोग महिला संगठन के सहयोग से गांवों की आंगनवाड़ी एवं चौपाल निर्माण, गलियों और सड़कों के निर्माण, कब्रिस्तान की चाहरदीवारी एवं मिट्टी भराई, शौचालय निर्माण आदि कार्यों को संपन्न कराने में किया गया।

नूंह जिले में महिलाओं की भागीदारी इसलिये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस जिले में शौचालयों की संख्या 47.8 प्रतिशत है, जो कि सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन के चलते बहुत ही चिंतनीय है। शौचालय न होने की वजह से सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। महिलाएं लाजशर्म की वजह से वक्त पर शौच नहीं जा पातीं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। घरों से बाहर खुले में शौच जाने पर अनहोनी का भी डर बना रहता है। महिला संगठनों ने गाँवों में शौचालयों एवं साफ–सफाई से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान की चर्चा अपनी–अपनी ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति में कीं। समिति में आने वाले बजट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कीं। कुछ गाँव में ऐसी समस्याओं के निपटाने के लिए महिला संगठनों ने स्वयं कार्यों की जिम्मेदारी लेकर पूर्ण कराया।

वर्ष 2015 में ही स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों ने ग्राम स्वच्छता के लिए 37 गाँवों में कुल 1332 शौचालय बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्य साफ–सफाई के कार्यों में समिति के फण्ड को भी लगाया। जिले के 0–5 आयु वर्ग के बच्चों को स्वस्थ भविष्य देने के लिए इन्द्रधनुष कार्यक्रम में महिला संगठन ने विशिष्ट योगदान दिया। संगठन के प्रयास के फलस्वरूप पिछले कुछ महीनों में कुल 2500 बच्चों का टीकाकरण कराया गया, जिससे बच्चों को सात खतरनाक बीमारियों जैसे–गलघोटू, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हिपेटाइटिस–बी से सुरक्षित किया जा सकता है।

फिरोजपुर खंड के गाँव मुण्डाका तथा ब्लॉक तावडू के गाँव उटोंन एवं चाहलका में संगठन के सहयोग से पीने योग्य पानी के लिए संग्रहण टैंक का निर्माण किया गया, जिससे वर्षभर ग्रामीणों एवं स्कूल के बच्चों के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सका। गाँव चाहलका में ही सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय बनवाकर बड़ी उम्र की लड़कियों की पढ़ाई में बाधा का निपटान किया गया। गाँव चाहलका में कीचड़ एवं पानी से भरी गलियों की वजह से होने वाली समस्याओं को लेकर महिला संगठन ने गाँव के सरपंच

पर दबाव बनाकर गलियों का पुनर्निर्माण कराया, जिससे ग्रामीणों की आने–जाने की समस्या के साथ–साथ गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल सका। नूंह खंड के गाँव भडोजी में सैनी परिवार के मुखिया की मौत होने पर आर्थिक मदद दी गई।

नगीना खण्ड के उलेटा एवं मोहम्मदनगर के गरीब परिवारों को आवासीय भूखण्ड की रजिस्ट्री एवं कब्जा दिलवाने में संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को महात्मा गाँधी ग्रामीण आवास योजना के तहत् पंचायत पात्र परिवारों को घर बनाने हेतु पंचायत के पास मौजूद जमीन से प्लॉट काटकर प्रदान करती है। इस योजना के अनुसार–वर्ष 2015 में उलेटा एवं मोहम्मदनगर गाँवों में गरीब परिवारों को जमीन आबंटित करने के कई महीनों बाद भी उन्हें जमीन पर न तो कब्जा मिला, न ही उन्हें रजिस्ट्री के कागजात दिए गए, जिससे वे परिवार अपना मालिकाना हक पाने में असमर्थ थे। अभी कुछ समय पहले ही महिला संगठन (स्थानीय महिलाओं का गठित समूह) ने जिला कार्यालय में आवाज उठाई एवं गरीब परिवारों को पैमाइश दिलाकर कब्जा दिलाया और रजिस्ट्री के कागजात भी दिलाने में सफलता हासिल की।

महिला संगठन ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को गति देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे इस कार्यक्रम का लाभ अधिक–से–अधिक लाभार्थी ले सकें। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली संस्था (राज्य संसाधन केंद्र, रोहतक) के कर्मचारियों से मिलकर संगठन की महिलाओं ने नूंह जिले की लगभग 16 पंचायतों के लोगों को साक्षरता मिशन के विषय में सूचना दी तथा अपनी देखरेख में इस योजना के तहत् होने वाली परीक्षाओं का आयोजन अपने–अपने गांवों में कराया। इस तरह संगठन के सदस्यों ने सरकारी विभागों के साथ मिलकर एक अच्छा उदाहरण पेश किया।

सहगल फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित महिला संगठन आज समस्त जिले में एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत किये जाते हैं, जो सरकारी ग्रामीण योजनाओं को लागू करवाने एवं अन्य विकास कार्यों को करने में पूर्णतया सक्षम हैं। महिला संगठनों की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, जिनसे महिला संगठन का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने अपनी रोजमर्रे की जरुरतों को हासिल करने के लिए संघर्ष करना अब भली–भांति सीख लिया है और अहम् मुद्दों पर सफलता भी प्राप्त की है। गाँव का सर्वांगीण विकास सही मायने में तभी संभव हैं, जब समुदाय के प्रत्येक नागरिक, वर्ग, जाति, पुरुष एवं महिला की भागीदारी हों।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत ग्राम विकास की जो ऐतिहासिक शुरुआत हुई है, उसकी सफलता भी तभी मिल सकती है, जब हम महिलाओं की भागीदारी के साथ–साथ उनके अधिकार सुनिश्चित करें और सही प्रशिक्षित करके अधिक सशक्त बनाएं। इस प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निरंतर प्रगति के रास्ते पर चलते रहने से पंचायतों एवं ग्रामीण विकास के कार्यों में अधिक–से–अधिक सफलता हासिल की जा सकती है और पंचायतों के स्थानीय स्वशासन संरचना को सही अर्थों में स्थापित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. A.Manjri. Essay on participation of Rural women in National Development. Accessed 0n 17th April 2017 http://www.shareyouressays.com/123742/essay-on-participation-of-rural-women-in-national-development-in-hindi
2. http://sbm.gov.in/sbmreport/Report/Physical/SBM_DistrictOverAllStatus.aspx
3. सहगल फाउंडेशन वार्षिक प्रतिवेदन–2015

□□

सम्पर्क : सहगल फाउण्डेशन, प्लॉट नं.-34, सेक्टर-44, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव-122003, हरियाणा

ईमेल : hbsharma69@gmail.com

कवि की पंक्तियां

प्रकृति से प्रेम

करो प्रेम सबसे, करो प्रेम प्रकृति से
प्रकृति बहुत सूबसूरत है, मगर बन रही इनसानी
दूसरा आज यह बदसूरत है
कोई न बच पाया इसके प्रकोप से
और इसको दौड़ने के आरोप से
प्रकृति एक समूचा संसार है
सभी के जीवन का एक भण्डार है
प्रकृति है भगवान की देन,
न है इसका कोई भेदभाव
न कोई इसका लेन–देन,
प्रकृति बहुत सूबसूरत है
करो प्रेम सबसे, करो प्रेम प्रकृति से।

कवि गुल ान (गुरु प्रका ा वर्मा)

सम्पर्क: 348/4, गोविन्दपुरी-कालकाजी, नईदिल्ली-110019